involved in the Gujarat Government's resolution and implementation thereof; and

(c) the steps taken by Government to prevent such violation?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

India's Stand in Second Earth Summit

1909. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Enrironment activist Vandana Shiva's reported statement in the Pioneer dated July 3, 1997 that Indian team to the Second Earth Summit, New York confined more to the trade agenda, than adopting an aggressive stand on sustainability agenda; and

(b) if so, what precise stand was taken by the Indian team about sustainability aspect of the GATT agenda, stressing the need for adoption of eco-friendly technologies for development?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) The Indian delegation to the United Nations General Assembly Special Session held at New York in June, 1997 to review the implementation of Agenda 21, stressed the need to ensure that there is a balanced and integrated approach to trade and sustainable development which is consistent with an open, rule-based, non-discriminatory, equitable, secure and transparant multilateral trading system. The WTO, UNEP and UNCTAD should consider ways to make trade and environment mutually supportive, including through due respect to the objectives and principles of the multilateral trading system and to the provisions of multilateral environmental agreements.

It was further emphasized that access to and transfer of environmentally sound technology on favourable terms, in particular to developing countries, should be promoted. This should include facilitating the transfer of privately owned technology on concessional terms as well as to developing countries.

These views were accepted in the final document in the Session.

लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करना

1910. श्री मूल चन्द मीणा:
श्री अजीत जोगी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राप्त किए गए, स्वीकार किए गए तथा अस्वीकार किए गए आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या निजी वन क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए भी पहले से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफउद्दीन सोज़): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र में काष्ठ पर आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए मंत्रालय में 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

क्रमांक	प्रस्ताव का नाम	राज्य	शामिल किया गया वन क्षेत्र	स्थिति
1.	राज्य वन निगम द्वारा स्थापित आरा मिलों को नियमित करना	उत्तर प्रदेश	0.25 है०	प्रस्ताव में आवश्यक ब्यौरे की कमी थी जिसको राज्य सरकार से मांगा गया है और उनकी प्रतीक्षा है
2.	सारूगढ़ में वन विकास निगम की आरा मिल	पश्चिम बंगाल	0.46 है०	अनुमोदित
3.	मदारीहाट में वन विकास निगम की आरा मिल	पश्चिम बंगाल	1.83 है०	अनुमोदित
4.	भूटाबारी में वन विकास निगम की आरा मिल	पश्चिम बंगाल	0.65 है०	अनुमोदित

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके तहत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार ऐसी समस्त वन भूमि, जोकि सरकारी रिकार्डों के वन के रूप में अधिसूचित की गई है, को गैर-वानिकी प्रयोजनों के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

पक्षियों के संरक्षण के लिए परियोजना

1911. **श्री नागमणि:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई परियोजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य और कार्य क्या हैं और इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है और यह परियोजना कब से शुरू हुई है और इसे कौन-सी एजेंसी कार्यान्वित कर रही है;

(ग) जिन उद्देश्यों के लिए यह परियोजना शुरु की गई थी, उनकी प्राप्ति में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या हाल ही में इसके कार्यकरण संबंधी कोई समीक्षा शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफउद्दीन सोज़): (क) पक्षियों के संरक्षण के लिए इस मंत्रालय द्वारा अलग से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता" से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों को चयनित राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के संरक्षण के लिए निधियां मुहैया की जा रही हैं। इनमें कई पक्षी अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

Smuggling of Ivory Products

1912. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the annual estimated value of ivory and ivory products smuggled out of the country in recent years;

(b) the details of the measures undertaken to minimise the menace; and